आंध्र प्रदेश राज्य

बनाम

अब्दुल खुद्दूस (मृत) जरीये विधिक प्रतिनिधी एवं अन्य

29 नवंबर, 2007

[तरुण चटर्जी और दलवीर भंडारी, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 226-रिट याचिका-एपी लैंड ग्रैबिंग (निषेध) अधिनियम, 1982 के तहत विशेष न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार-हेल्ड: उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार में, विशेष न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्षों में तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब निष्कर्ष बिना किसी सबूत के या अनुमानों या धारणाओं पर आधारित हों और यदि कोई उचित व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, विशेष न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पर पहुंचें-तथ्यों के आधार पर, विशेष न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को, किसी भी तरह से, बिना किसी सबूत के आधार पर या अनुमानों या अनुमानों से घिरा हुआ नहीं कहा जा सकता है और वह प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से उत्तरदाताओं के स्वामित्व के सवाल पर विशेष न्यायालय का निष्कर्ष प्रासंगिक सबूतों - मौखिक या दस्तावेजी दोनों - के

विचार पर आधारित था, इसके अलावा, न तो किसी भी प्रासंगिक सामग्री को उसके द्वारा विचार से बाहर रखा गया था और न ही किसी अप्रासंगिक सामग्री पर भरोसा किया गया था। इसके निष्कर्षों को दर्ज करने में - इसके अलावा, चूंकि तथ्यों पर यह पाया गया है कि उत्तरदाता न तो यह साबित कर सके कि उन्होंने अनुसूची भूमि के संबंध में प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व हासिल किया है और न ही यह साबित किया जा सका कि अनुसूची भूमि गांधी हिल सोसाइटी की थी, यह इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि भूमि केवल राज्य की होगी जिसे उत्तरदाताओं ने हड़प लिया था।यह भी रिकार्ड में रखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय, जबकि विशेष न्यायालय के निष्कर्षों को उलटते हुए भी इस तथ्य के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका कि उत्तरदाताओं ने प्रतिकूल कब्जे से अनुसूचित भूमि के संबंध में अपना स्वामित्व पूरा कर लिया था या कि अनुसूचित भूमि गांधी हिल सोसाइटी की थी। यह उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं था, अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, विशेष न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्यों के निष्कर्षों को रद्द कर सके, जो ठोस विचार पर आधारित रिकॉर्ड-उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया है- हालांकि, चूंकि उत्तरदाताओं ने अनुसूचित भूमि पर निर्माण किया है और विशेष न्यायालय ने मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया है ताकि अनुसूचित भूमि के संबंध में उत्तरदाताओं का शीर्षक सही हो, उत्तरदाताओं को विशेष न्यायालय के निर्देशानुसार राशि का भुगतान करना होगा और इस घटना में, उत्तरदाता उक्त राशि जमा करने में विफल रहे, विशेष

अदालत के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दी जाएगी और यह अपीलकर्ता के लिए कानून के अनुसार अनुसूची भूमि की वसूली के लिए खुला होगा।

कोंडा लशमाना बापूजी बनाम आंध्र प्रदेश और अन्य, [2002] 3 एससीसी 258, पर भरोसा किया-

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2000 की सिविल अपील संख्या 7360

हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के डब्ल्यूपी संख्या 6452/1995 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 13.10.1998 से।

एचएस गुरुराजा राव, मनोज सक्सेना, रजनीश केआर. सिंह, राहुल शुक्ला और टीवी जॉर्ज अपीलकर्ता की ओर से।

उत्तरदाताओं के लिए बी. सुनीता राव।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था।

<u>आदेश</u>

1. यह अपील 1995 के डब्लूपी संख्या 6452 में हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के 13 अक्टूबर 1998 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने रिट याचिका दायर करने की अनुमति दी थी। उत्तरदाताओं द्वारा और हैदराबाद में आंध्र प्रदेश भूमि हथियाने (निषेध) अधिनियम, 1982 (संक्षेप

में "विशेष न्यायालय") के तहत विशेष न्यायालय द्वारा पारित 9 जून, 1994 के आदेश को रद्द कर दिया।

2. इस अपील में निर्णय लेने की आवश्यकता वाला एकमात्र प्रश्न यह है, "क्या उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, आंध्र के तहत विशेष न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्ष को रद्द कर सकता है" प्रदेश भूमि हथियाने (निषेध) अधिनियम, 1982 (संक्षेप में "अधिनियम") जब विशेष न्यायालय के तथ्य की ऐसी खोज रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद की गई थी और इसे विकृत या मनमाना नहीं कहा जा सकता है?"

3. संक्षेप में कहा गया है, इस अपील को दायर करने के लिए अग्रणी तथ्य यह है कि अपीलकर्ता, आंध्र प्रदेश राज्य, ने विशेष न्यायालय में उत्तरदाताओं के खिलाफ अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, आरोप लगाया गया कि पहला प्रतिवादी कब्जे में था। वार्ड नंबर 5, ब्लॉक नंबर 1, विजयवाड़ा में 470 वर्ग गज भूमि, जिसमें से 220 वर्ग गज एनटीएस नंबर 26 में स्थित है, जो विजयवाड़ा शहर के पुराने एनटीएस नंबर 17/1-ए/1-ए से संबंधित है। (संक्षेप में "अनुसूची भूमि") अवैध अतिक्रमण के माध्यम से था। अपीलकर्ता ने आगे शिकायत की कि दूसरे और तीसरे प्रतिवादी, मूल प्रतिवादी नंबर 2 के उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते, 540 वर्ग गज भूमि पर कब्जा कर रहे थे, जिसमें से 190 वर्ग गज एनटीएस

नंबर 26 में भी स्थित थे। पुराने एनटीएस नंबर से सहसंबद्ध विजयवाड़ा शहर का 17/1-ए/1-ए (संक्षेप में "अनुसूची भूमि") अवैध अतिक्रमण के माध्यम से था। तदनुसार, अपीलकर्ता, आंध्र प्रदेश राज्य ने एक घोषणा के लिए प्रार्थना की थी कि प्रतिवादी अधिनियम के अर्थ के तहत भूमि हड़पने वाले थे और अपीलकर्ता अनुसूचित भूमि का मालिक था।

4. उत्तरदाताओं ने अपनी आपत्ति में इस बात से इनकार किया कि वे अनुसूची भूमि के संबंध में भूमि हड़पने वाले थे और दलील दी कि उनके पूर्ववर्तियों ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से भूमि का स्वामित्व हासिल कर लिया था और वैकल्पिक रूप से, उनके अनुसार, अनुसूची भूमि गांधी हिल सोसायटी की थी और इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ता की भूमि को हड़पने का सवाल ही नहीं उठता। तदनुसार, उन्होंने अनुरोध किया कि एपी राज्य द्वारा दायर अधिनियम के तहत आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

5. पार्टियों पर मुकदमा चला और उन्हें अपने संबंधित मामलों के समर्थन में सबूत पेश करने की अनुमति दी गई।

6. विशेष न्यायालय, जिसके समक्ष अपीलकर्ता द्वारा भूमि हड़पने के लिए आवेदन दायर किया गया था, ने रिकॉर्ड पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद माना कि प्रतिवादी अधिनियम के अर्थ के तहत भूमि हड़पने वाले थे। विशेष अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों और पक्षों द्वारा पेश किए गए सबूतों पर विचार करते हुए यह भी

माना कि उत्तरदाता यह साबित करने में असफल रहे कि उन्होंने अनुसूचित भूमि के संबंध में प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व हासिल कर लिया है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह भी कहा गया कि उत्तरदाता यह साबित करने में विफल रहे कि शेड्यूल भूमि गांधी हिल सोसाइटी की थी। हालाँकि, विशेष न्यायालय ने यह पाया कि उत्तरदाताओं ने अनुसूचित भूमि पर निर्माण किया था। उत्तरदाताओं को उनके द्वारा हड़पी गई अनुसूचित भूमि के बाजार मूल्य का भुगतान करने की स्वतंत्रता दी गई ताकि उनके द्वारा उसी का शीर्षक पूरा किया जा सके। तदनुसार, विशेष अदालत ने प्रथम प्रतिवादी को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। 4,40,000/- और दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं को अपीलार्थी को 12 मासिक किश्तों द्वारा 3,80,000/- रु. का भुगतान करना होगा।

7. विशेष न्यायालय के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, उत्तरदाताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसे अनुमति दी गई, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, और विशेष न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया था।

8. इसलिए, इस अपील के उचित निपटान के लिए, हमारे लिए इस स्तर पर विशेष न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्षों पर विचार करना आवश्यक होगा। विशेष न्यायालय साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद तथ्य के निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा था - मौखिक और रिकॉर्ड पर दस्तावेजी: -

(i) प्रदर्शनी ए1 पुराने टीएस नंबर 17/1ए/1ए में भूमि के संबंध में टाउन सर्वे भूमि रजिस्टर का उद्धरण था और इसका वर्गीकरण 'पोरम्बोक' के रूप में दिखाया गया था। प्रदर्शनी ए2 1399-1400 की फ़सलीज़ के लिए उक्त भूमि के संबंध में अदंगल का उद्धरण था, जिसमें अनुसूची भूमि को कॉलम नंबर 6 में 'कोंडा पोरम्बोक' के रूप में वर्णित किया गया था।

(ii) प्रथम प्रतिवादी का नाम प्रदर्शनी ए2 में 220 वर्ग गज की सीमा में अतिक्रमणकर्ता के रूप में दिखाया गया था। प्रदर्शन A3, अदांगल उद्धरण में, दूसरे प्रतिवादी का नाम 190 वर्ग गज की सीमा में अतिक्रमणकर्ता के रूप में दिखाया गया था और प्रतिवादी संख्या 3 और 4, जो दूसरे प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि थे, उस 190 पर कब्जा जारी रखे हुए थे। प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु के बाद वर्ग गज।

(iii) प्रदर्शनी ए4 प्रतिवादी संख्या 1, 3 और 4 द्वारा अतिक्रमण किए गए विस्तार को दर्शाने वाला रेखाचित्र था।

(iv) प्रदर्शनी ए5 अतिक्रमित विस्तार को दर्शाने वाला एक और रेखाचित्र था।

(v) पीडब्लू3 के साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, यह पाया गया कि प्रदर्शनी ए13 1965 की सर्वेक्षण योजना का एक सच्चा उद्धरण था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, 3 और 4 द्वारा पकड़ी गई सीमाएँ दिखाई गई थीं, जो एनटीएस संख्या 26 में लाल रंग से अंकित थीं।

(vi) पीडब्लू3 के साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए, यह पाया गया कि गांधी हिल सोसाइटी की भूमि 1965 के सर्वेक्षण के अनुसार एनटीएस नंबर 52 में थी, जो पुराने एनटीएस नंबर 15-अल भाग से संबंधित थी।

(vii) पीडब्लू-3 की जिरह पर भरोसा करते हुए, यह भी माना गया कि एनटीएस नंबर 52 में केवल 7 एकड़ या उससे अधिक की सीमा गांधी हिल सोसाइटी की थी और सोसाइटी के पास एनटीएस नंबर 26. की सीमा में कभी कोई स्वामित्व नहीं था।

(viii) यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1, 3 और 4 के पास कितने समय से वह जमीन थी जो उनके द्वारा हड़पी हुई दिखाई गई थी।

(ix) प्रदर्शनी ए12 पर भरोसा करते हुए, यह भी माना गया कि एनटीएस नंबर 52 विजयवाड़ा के पुराने एनटीएस नंबर 15-ए1 भाग से संबंधित था और एनटीएस नंबर 26 पुराने एनटीएस नंबर 17/1ए-भाग से संबंधित था। तदनुसार, विशेष न्यायालय ने माना कि प्रदर्शनी ए12 में प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि गांधी हिल सोसाइटी का वर्ष 1965 में सर्वेक्षण के अनुसरण में गठित एनटीएस नंबर 26 से कोई लेना-देना नहीं है और इसलिए, यह स्पष्ट रूप से साबित होता है। PW1 और 2 के साक्ष्य कि अनुसूची भूमि, जो कि प्रदर्शन A8 और सभी द्वारा कवर की गई साइटों के पूर्व में स्थित 410 वर्ग गज की सीमा थी, सरकार से संबंधित एनटीएस

नंबर 26 में थी, न कि एनटीएस नंबर 52 में थी। गांधी हिल सोसायटी को।

(x) स्वामित्व विलेख प्रस्तुत न करने के लिए उत्तरदाताओं के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया था, जिन्होंने केवल प्रदर्शनी ए-8 पर भरोसा किया था, जो प्रतिवादी संख्या 1 और प्रदर्शनी ए 11 के पक्ष में था, जो देर से प्रतिवादी संख्या 2. के पक्ष में था।

(xi) प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वीकार किया कि उसने प्रदर्शनी ए 4 के अनुसार 220 वर्ग गज के पूर्व में 250 वर्ग गज की दूरी खरीदी थी, जिसे उसके द्वारा हड़प लिया गया था और यह भी प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा स्वीकार किया गया था कि उसकी मां प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रदर्शनी ए 11 के मूल के तहत केवल 350 वर्ग गज की सीमा खरीदी थी और 190 वर्ग गज की सीमा की साइट उसके द्वारा हड़प ली गई थी और प्रतिवादी संख्या 4 उस बिक्री विलेख में शामिल नहीं थी। .

(xii) जहां तक उत्तरदाताओं के प्रतिकूल कब्जे के मामले का सवाल है, यह पाया गया कि उत्तरदाता यह साबित करने में असफल रहे कि उन्होंने प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व हासिल किया था।

तदनुसार, विशेष न्यायालय ने अपने निष्कर्षों पर विचार करने के बाद आवेदन को यह कहते हुए अनुमति दे दी कि भूमि राज्य की है और प्रथम प्रतिवादी को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। 4,40,000/-

और दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं को अपीलार्थी को 12 मासिक किश्तों द्वारा 3,80,000/- रु. का भुगतान करना होगा।

9. यह विशेष न्यायालय का आदेश है, जिसे उत्तरदाताओं ने रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। इस समय, हम अब इस बात पर विचार कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में, विशेष न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्ष में कब हस्तक्षेप कर सकता है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार में हैसंविधान के अनुसार, विशेष न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्यों के निष्कर्षों में केवल तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब निष्कर्ष बिना किसी सबूत के या अनुमानों या अनुमानों पर आधारित हों और यदि कोई भी उचित व्यक्ति दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष पर न पहुंचे। विशेष न्यायालय. इसलिए, यह स्पष्ट है कि केवल इन विशेष परिस्थितियों में ही उच्च न्यायालय विशेष न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए खुला होगा। कोंडा में लक्ष्मण बापूजी बनाम. सरकार. आंध्र प्रदेश और अन्य 2002 (3) एससीसी 258, इस अदालत ने अधिनियम के प्रावधानों से निपटते हुए इस सवाल का फैसला किया कि उच्च न्यायालय, अपने रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, तथ्यों के निष्कर्षों में कब हस्तक्षेप कर सकता है। विशेष न्यायालय ने पैरा 49 में निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"पहले प्रतिवादी और अपीलकर्ता और उसके पट्टेदार इनामदार के स्वामित्व के सवाल पर विशेष न्यायालय के फैसले का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर हम संतुष्ट हैं कि न तो किसी भी प्रासंगिक सामग्री को विचार से बाहर रखा गया था और न ही किसी अप्रासंगिक सामग्री पर भरोसा किया गया था। विशेष न्यायालय ने अपने निष्कर्षों को दर्ज किया। इसलिए, उच्च न्यायालय के लिए उन निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में विशेष न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप न करके कोई कानूनी त्रुटि नहीं की। पहले प्रतिवादी का शीर्षक और विवाद में भूमि पर अपीलकर्ता के पास स्वामित्व का अभाव है। (देखें: उमर सले मोहम्मद सैत वी. सीआईटी)"

10. हम पहले ही विशेष न्यायालय के निष्कर्षों पर चर्चा कर चुके हैं और उसी से हमें पता चलता है कि विशेष न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष, किसी भी तरह से, बिना किसी सबूत के आधार पर या अनुमानों या अनुमानों से घिरे हुए नहीं कहे जा सकते हैं और कि प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से उत्तरदाताओं के स्वामित्व के प्रश्न पर विशेष न्यायालय का निष्कर्ष मौखिक या दस्तावेजी दोनों तरह के प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार पर आधारित था। इसके अलावा, हम विशेष न्यायालय के आदेश से यह भी

पाते हैं कि न तो किसी भी प्रासंगिक सामग्री को उसके द्वारा विचार से बाहर रखा गया था और न ही उसके निष्कर्षों को दर्ज करने में किसी अप्रासंगिक सामग्री पर भरोसा किया गया था। पुनरावृत्ति के जोखिम पर, हम कह सकते हैं कि विशेष न्यायालय साक्ष्य में गया था, रिकॉर्ड पर दस्तावेजी साक्ष्य सहित दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया गया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुसूचित भूमि गांधी हिल सोसाइटी की नहीं थी और उत्तरदाता यह साबित नहीं कर सके कि उनके पास अनुसूची भूमि के संबंध में सही स्वामित्व था। प्रतिकूल कब्जे का. इसके अलावा, हमारा विचार है कि चूंकि तथ्यों पर यह पाया गया है कि उत्तरदाता न तो यह साबित कर सके कि उन्होंने अनुसूचित भूमि के संबंध में प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व हासिल किया था और न ही यह साबित किया जा सका कि अनुसूचित भूमि उनकी थी। गांधी हिल सोसायटी के अनुसार, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जमीन केवल राज्य की होगी जिसे प्रतिवादियों ने हड़प लिया। यह भी रिकार्ड में रखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय, जबकि विशेष न्यायालय के निष्कर्षों को उलटते हुए भी इस तथ्य के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका कि उत्तरदाताओं ने प्रतिकूल कब्जे से अनुसूचित भूमि के संबंध में अपना स्वामित्व पूरा कर लिया था या कि अनुसूचित भूमि गांधी हिल सोसाइटी की थी। ऐसी स्थिति होने के कारण, हम उच्च न्यायालय के आदेश को कायम रखने में असमर्थ हैं, जिसने विशेष न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्यों के निष्कर्षों को खारिज कर दिया था, जो, हमारे विचार में, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर विचार

करने के बाद निकाले गए थे और जो कल्पना की किसी भी सीमा से, यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी साक्ष्य या अनुमान या अनुमान पर आधारित है और इसलिए, यह उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं था कि वह अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, प्राप्त तथ्य के निष्कर्षों को रद्द कर दे। विशेष न्यायालय जो रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के गहन विचार-विमर्श पर आधारित थे।

11. तदनुसार, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है। इस आदेश से अलग होने से पहले, हम इसे रिकॉर्ड पर रख सकते हैं कि विशेष न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया था कि उत्तरदाताओं ने अनुसूची भूमि पर निर्माण किया है और इसलिए, मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया था ताकि अनुसूची के संबंध में उत्तरदाताओं का अधिकार हो सके। भूमि सिद्ध हो गयी है. ऐसी स्थिति होने पर, उत्तरदाताओं के लिए यह खुला होगा कि वे विशेष न्यायालय द्वारा निर्देशित राशि का भुगतान करें और यदि विशेष न्यायालय द्वारा निर्देशित उक्त राशि का भुगतान इस तिथि से चार महीने के भीतर किया जाता है, तो आवेदन दायर किया जाएगा। अपीलकर्ता को उस निर्देश के साथ निपटाया जाएगा और उस स्थिति में, उत्तरदाता उक्त राशि जमा करने में विफल रहेंगे।

12. उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है और विशेष न्यायालय के फैसले को बहाल किया जाता है।

13. सिविल अपील तदनुसार लागतों के संबंध में बिना किसी आदेश के निपटा दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रिंकू कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।